

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024—आश्विन 26, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्र. ई-5-870-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 5, 6 एवं 12, 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. ई-1-206-2024-5-एक.—श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

5069

क्र. ई-5-1043-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, (2016), अपर कलेक्टर, जिला सतना को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 13 एवं 19, 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. ई-1-238-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 12,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	तालिका	
		मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. एफ 05-10-2022-साप्रावि कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पीपीएस, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1713-(दो-1-18-2023) दिनांक 27 फरवरी 2024 के अनुक्रम में दिनांक 12 से 17 फरवरी 2024 तक कुल छः दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्र. एफ-2-0014-2023-व-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2024 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 14-15 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले उनके गृह नगर अलवर (राजस्थान) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल का चालू कार्य श्री चंद्रशेखर पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त, टी. टी. नगर, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मयूर खंडेलवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयूर खंडेलवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 134-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2024 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर के स्थान पर भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत अंडमान निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री विजय कुमार खत्री — स्वयं
2. श्रीमती विजया खत्री — पत्नी

(2) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे के अवकाश अवधि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री अंकित शुक्ला, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेडियो, सीसीटीव्ही, रेडियो मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1 (ए) 18-2004-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन, को दिनांक 20 से 26 सितम्बर 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री अभय सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन का चालू कार्य श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अभय सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अभय सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा, एन., भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 व 28-29 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा, एन., भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा, एन., भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा, एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024

क्र. 3720-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन वर्ष 2025 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री संजय कृष्ण जोशी	03-01-1965	02-01-2025	31-01-2025
2	श्री राजीव कुमार कर्महे	11-01-1965	10-01-2025	31-01-2025
3	श्री रामानन्द चन्द	15-01-1965	14-01-2025	31-01-2025
4	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जून.)	15-01-1965	14-01-2025	31-01-2025
5	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा	11-02-1965	10-02-2025	28-02-2025
6	श्री पदम चंद गुप्ता	17-03-1965	16-03-2025	31-03-2025
7	श्री प्रमोद कुमार	19-03-1965	18-03-2025	31-03-2025
8	श्री मोहम्मद मूसा खान	01-04-1965	31-03-2025	31-03-2025
9	श्री प्रदीप राठौर	14-05-1965	13-05-2025	31-05-2025
10	श्री सैफी दाऊदी	14-06-1965	13-06-2025	30-06-2025
11	श्री रामगोपाल प्रजापति	14-06-1965	13-06-2025	30-06-2025
12	श्री मोहम्मद अनीस खान	01-07-1965	30-06-2025	30-06-2025
13	श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर (जून.)	06-07-1965	05-07-2025	31-07-2025
14	श्रीमती किरण सिंह	13-07-1965	12-07-2025	31-07-2025
15	श्री धर्मपाल सिंह सिवाच	16-07-1965	15-07-2025	31-07-2025
16	श्री मो. सय्यदुल अबरार अन्सारी	25-07-1965	24-07-2025	31-07-2025
17	श्री पवन कुमार शर्मा	01-08-1965	31-07-2025	31-07-2025
18	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	07-08-1965	06-08-2025	31-08-2025
19	श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाहा	12-08-1965	11-08-2025	31-08-2025
20	श्री राजेश कुमार गुप्ता	15-08-1965	14-08-2025	31-08-2025
21	श्री अजय कुमार सिंह	15-08-1965	14-08-2025	31-08-2025
22	श्री राजेश नदेश्वर	20-09-1965	19-09-2025	30-09-2025
23	श्री संजय कुमार पाण्डेय	01-10-1965	30-09-2025	30-09-2025
24	श्री गिरीश दीक्षित	06-10-1965	05-10-2025	31-10-2025
25	श्री जयशंकर श्रीवास्तव	10-10-1965	09-10-2025	31-10-2025
26	श्रीमती सविता सिंह	18-10-1965	17-10-2025	31-10-2025
27	श्री विवेक कुमार गुप्ता	31-10-1965	30-10-2025	31-10-2025
28	श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल	03-11-1965	02-11-2025	30-11-2025
29	श्री राजा राम भारतीय	10-11-1965	09-11-2025	30-11-2025
30	श्री प्रकाश चन्द्र आर्य	12-12-1965	11-12-2025	31-12-2025
31	श्री अजय प्रकाश मिश्र	15-12-1965	14-12-2025	31-12-2025
32	श्री राजकुमार यादव	15-12-1965	14-12-2025	31-12-2025
33	श्री राजदीप सिंह ठाकुर	26-12-1965	25-12-2025	31-12-2025
34	श्री पूरन चन्द्र गुप्ता	01-01-1966	31-12-2025	31-12-2025
35	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	01-01-1966	31-12-2025	31-12-2025
36	श्री दगाडू सिंह चौहान	01-01-1966	31-12-2025	31-12-2025

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्र. 3894-इक्कीस-ब (एक)-2024.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है।

No. 3894-XXI-B(I),-2024.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Sanjeev Sachdeva, Judge, Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect.

पंजी क्र. 3902-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, माननीय राज्यपाल महोदय के विधि अधिकारी, राजभवन, भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल के पद पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2024

क्र. एफ-1-3-24-रा. स.-यू. ए.-1-1157.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, एतद्द्वारा, प्रो. राकेश सिंघई, प्रोफेसर एवं निदेशक, युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति।

कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

क्र. एफ-1-1-24-रा. स.-यू. ए.-1-1169.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, एतद्द्वारा, प्रो. अर्पण भारद्वाज, प्रोफेसर एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

संधवा विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4437-वि. यो.-संधवा-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि संधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, संधवा, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संधवा विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-15	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

प्ररूप-1

[नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए]

उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्र. 4587-14-10-24.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 23-ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद्वारा, भोपाल निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-

अनुसूची
(उत्पादन क्षेत्र)

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भोपाल विकास योजना, 2005 का निवेश क्षेत्र.	विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.	मार्ग से प्रभावित सम्पूर्ण रकबा.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

प्ररूप-2

[नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए]

प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्र. 4599-14-10-24.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 2 के खण्ड (गणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा, भोपाल निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	खसरा क्रमांक (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
1.	भोपाल विकास योजना, 2005 का निवेश क्षेत्र.	विकास योजना, 2005 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.	मार्ग की चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

उज्जैन विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4602-वि. यो.-उज्जैन-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

उज्जैन विकास योजना, 2035 के अध्याय-6 की कंडिका 6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र (सिंहस्थ मेला क्षेत्र) के बिन्दु क्रमांक-2 (iv) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र (सिंहस्थ मेला क्षेत्र)

2. (iv) अधिकतम ऊंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 अगस्त 2024

क्र. 691-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर नगर	रौसर	1.605	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म. प्र.)	रीवा जिले के रौसर चौराहा से कुतुलिया मार्ग में बीहर नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुँचमार्ग का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 सितम्बर 2024

क्र. 778-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योँथर	डीह	0.260	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म. प्र.)	रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह) पर जलमगनीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्र. 792-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोटा	0.680	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.)	रीवा जिले के सिगमा टोला हटा (हटहा) सिगमा सेमरिया मार्ग में कुरवाई नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

क्र. 2756-भू-अर्जन-2024-रा.प्र. क्र. 0001-अ-82-2024-25.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) कस्बा—उज्जैन
(घ) अर्जित रकबा—0.0311 हेक्टेयर.

क्र.	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित रकबा (हेक्टर में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2405/2	0.050	0.0311	उक्त भूमियों पर 07 निर्मित मकान का भी अधिग्रहण किया जा रहा है.
2	2405/3	0.050		
3	2405/4	0.045		
4	2405/5	0.052		
कुल अधिग्रहित रकबा			0.0311	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—रेल्वे स्टेशन उज्जैन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा संभागीय प्रबंधक सड़क विकास निगम, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 3 सितम्बर 2024

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

क्र. भू-अर्जन-2024-7371-रा.प्र.क्र. 0001-अ-82-2024-25.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.	11.81 हे.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण :-

(क) जिला	-	उज्जैन
(ख) तहसील	-	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	-	माधौपुर
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	-	11.81

क्र.	सर्वे नंबर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	80	0.150	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
2.	89	0.410	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	90	0.590	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
4.	91	0.450		विस्तारीकरण हेतु.
5.	81/1	0.500		
6.	82/2	0.100		
7.	84	0.110		
8.	85/1	0.270		
9.	86	0.170		
10.	87	0.240		
11.	81/2	0.900		
12.	82/1	0.220		
13.	83	0.140		
14.	85/2	0.130		
15.	92	0.480		
16.	93/1	1.150		
17.	93/2	1.000		
18.	93/3/1	0.900		
19.	93/3/2	0.100		
20.	94/1	0.200		
21.	94/2	0.600		
22.	94/3	1.000		
23.	94/4/1/1	0.100		
24.	94/4/1/2	0.400		
25.	94/4/2	0.500		
26.	94/5/1	0.800		
27.	94/5/2	0.200		

योग . . . 11.810

- (2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7372-रा.प्र.क्र. 0007-अ-82-2024-25.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.	90.570 हे.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण :-

(क) जिला	-	उज्जैन
(ख) तहसील	-	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	-	चैनपुर हंसखेडी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	-	90.570 हे.

क्र.	सर्वे नंबर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	88/1/1/1	0.410	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
2.	88/1/1/2	1.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	88/1/2/1	0.800	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
4.	88/1/2/2	1.000		विस्तारीकरण हेतु.
5.	88/2/1	0.200		
6.	88/2/2	0.400		
7.	90/1/1	0.740		
8.	90/1/2	1.000		
9.	90/2/1	0.250		
10.	90/2/2	0.800		
11.	91	0.690		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	95	2.520	कार्यपालन यंत्रि	औद्योगिक क्षेत्र
13.	96	0.890	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
14.	98	1.220	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
15.	99	1.690		विस्तारीकरण हेतु.
16.	100/1	2.800		
17.	100/2	2.010		
18.	101	1.920		
19.	102/1	1.340		
20.	102/2	1.340		
21.	103/1	1.080		
22.	103/2	2.490		
23.	104/1	0.120		
24.	104/2	0.790		
25.	104/3	0.790		
26.	106/1	0.600		
27.	106/2	1.400		
28.	107	0.770		
29.	108/1	0.500		
30.	108/2	1.140		
31.	108/3	0.560		
32.	109/1	5.690		
33.	109/2	1.400		
34.	109/3/1	0.400		
35.	109/3/2	0.400		
36.	110/1	0.200		
37.	110/2/1	0.590		
38.	110/2/2	0.290		
39.	110/3/1	0.020		
40.	110/3/2	0.200		
41.	110/4/1	0.110		
42.	110/4/2	0.090		
43.	111	0.930		
44.	112/1/1	1.500		
45.	112/1/2	1.500		
46.	112/2	1.270		
47.	112/3	1.700		
48.	112/4/1	0.670		
49.	112/4/2	0.200		
50.	112/5	1.200		
51.	113	2.510		
52.	114/1	2.400		
53.	114/2/1	0.200		
54.	114/2/2/1	1.200		
55.	114/2/2/2	2.890		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56.	116/1	2.720	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
57.	116/2	0.110	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
58.	117/1/1	0.700	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
59.	117/1/2	0.700		विस्तारीकरण हेतु.
60.	117/2	0.700		
61.	118/1/1	0.120		
62.	118/1/2	0.230		
63.	118/2	0.350		
64.	118/3	0.360		
65.	118/4	0.360		
66.	119	0.310		
67.	120/1	0.200		
68.	120/2	0.050		
69.	121	0.310		
70.	122	0.360		
71.	123/1	0.080		
72.	123/2	0.440		
73.	124	0.360		
74.	125	1.590		
75.	126	2.420		
76.	127/1	0.080		
77.	127/2	0.750		
78.	127/3	0.500		
79.	127/4	0.540		
80.	127/5	0.200		
81.	128/1	0.120		
82.	128/2	0.160		
83.	128/3/1	0.410		
84.	128/3/2	0.400		
85.	129/1	0.470		
86.	129/2	0.420		
87.	129/3	0.780		
88.	130/1	0.450		
89.	130/2	1.020		
90.	131	0.640		
91.	132	1.640		
92.	133/1/1	0.180		
93.	133/1/2	0.180		
94.	133/2	0.700		
95.	134	0.660		
96.	135/1	0.100		
97.	135/2	0.500		
98.	135/3	0.400		
99.	135/4	0.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100.	135/5	0.290	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
101.	136	1.240	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
102.	137/1	0.480	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
103.	137/2	0.200		विस्तारीकरण हेतु.
104.	137/3	0.300		
105.	137/4	0.300		
106.	138	0.210		
107.	139	0.250		
108.	140/1/1	0.100		
109.	140/1/2	0.770		
110.	140/2/1/1	0.100		
111.	140/2/1/2	0.100		
112.	140/2/2	0.100		
113.	141/1	0.570		
114.	141/3	0.570		

कुल रकबा . . 90.570

- (2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्षों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7373-रा.प्र.क्र. 0003-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.	22.62 हे.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण :-

(क) जिला	-	उज्जैन
(ख) तहसील	-	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	-	पिपलौदा द्वारकाधीश
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	-	22.62 हे.

क्र.	सर्वे नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि रकबा (हे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	208	0.500	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
2.	217	0.500	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	218	0.670	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
4.	221/1	1.200		
5.	221/2	1.400		
6.	221/3	0.530		
7.	221/4	0.530		
8.	221/11	0.500		
9.	221/12	0.500		
10.	221/13	0.500		
11.	221/14	0.500		
12.	221/15	0.500		
13.	221/16	0.500		
14.	221/7	0.500		
15.	209/1	1.220		
16.	209/2	0.400		
17.	210/1	2.610		
18.	210/2	1.000		
19.	211	2.280		
20.	214	0.460		
21.	216	0.580		
22.	212	0.060		
23.	213	0.800		
24.	215	0.800		
25.	219/1/1	0.300		
26.	219/1/2/1	0.320		
27.	220/1/1	0.270		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	219/1/2/2	0.190	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
29.	220/1/2	0.110	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
30.	219/1/2/3	0.320	उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
31.	220/1/3	0.270		विस्तारीकरण हेतु.
32.	219/2/1	0.310		
33.	220/2/1	0.190		
34.	219/2/2	0.320		
35.	220/2/2	0.180		
36.	221/6	0.800		

कुल रकबा . . 22.62

- (2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7374-रा.प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.	31.550 हे.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण :-

(क) जिला	-	उज्जैन
(ख) तहसील	-	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	-	मुंजाखेड़ी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	-	31.550 हे.

क्र.	सर्वे नंबर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1/1	0.410	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
2.	1/2	0.200	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	2/1	0.800	उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
4.	2/2	0.150		
5.	3	0.500		
6.	4/1	0.050		
7.	4/2	0.300		
8.	4/3	0.130		
9.	5	0.050		
10.	6	0.400		
11.	7	0.330		
12.	8/1	0.170		
13.	8/2	1.210		
14.	9/1	0.100		
15.	9/2	0.190		
16.	33/1	0.020		
17.	33/2	0.460		
18.	33/3	0.150		
19.	33/4	0.060		
20.	35	0.420		
21.	37/1	1.520		
22.	37/2	0.180		
23.	38/1	0.170		
24.	38/2	0.460		
25.	38/3	0.090		
26.	39/1	0.790		
27.	39/2	0.500		
28.	40/1	0.120		
29.	40/2	0.250		
30.	42	0.150		
31.	43	0.110		
32.	44	1.630		
33.	45	0.050		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	46	0.120	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
35.	47	0.070	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
36.	48	0.020	उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
37.	49	0.800		विस्तारीकरण हेतु.
38.	54	0.660		
39.	55	1.690		
40.	56/1	0.070		
41.	56/2	0.060		
42.	56/3	0.060		
43.	56/4	0.060		
44.	57/1	1.030		
45.	57/2	1.040		
46.	59	0.800		
47.	60	0.800		
48.	61/1	0.500		
49.	61/2	0.300		
50.	67/1	0.240		
51.	67/2	0.300		
52.	67/3	0.140		
53.	67/4	0.570		
54.	67/5	0.560		
55.	41/1	0.500		
56.	41/2	0.100		
57.	53	0.100		
58.	68/1	0.180		
59.	68/2	0.200		
60.	68/3	0.200		
61.	68/4	0.200		
62.	69	0.870		
63.	71	0.760		
64.	72/1	0.310		
65.	72/2	0.620		
66.	75/1	0.800		
67.	75/2/1	0.200		
68.	75/2/2	0.050		
69.	10/1	0.750		
70.	10/2	0.600		
71.	11	0.440		
72.	13/1	1.220		
73.	13/2	0.410		
74.	13/3	0.210		
75.	76/1	0.260		
76.	76/2/1	0.260		
77.	76/2/2/1/1	0.080		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78.	76/2/2/1/2	0.120	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
79.	76/2/2/2	0.100	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
		कुल रकबा . . . 31.550		

- (2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7375-रा.प्र.क्र. 0005-अ-82-2024-25.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.	46.760 हे.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण :-

(क) जिला	-	उज्जैन
(ख) तहसील	-	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	-	गांवडी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	-	46.760 हे.

क्र.	सर्वे नंबर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	199	1.210	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
2.	200	0.370	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	198	0.100	उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
4.	197	0.560		विस्तारीकरण हेतु.
5.	196	0.580		
6.	195/1	0.630		
7.	235/2	0.590		
8.	235/1	0.600		
9.	234	1.180		
10.	233/2	0.790		
11.	233/1	0.390		
12.	232	0.400		
13.	231/2	1.000		
14.	203/3	0.600		
15.	203/2	0.680		
16.	203/1/2	0.200		
17.	203/1/1/2	0.100		
18.	203/1/1/1	0.460		
19.	202/3	0.500		
20.	202/2	0.510		
21.	202/1	1.010		
22.	201	2.090		
23.	229/1	0.690		
24.	230	2.090		
25.	220	0.830		
26.	221	0.250		
27.	222	0.220		
28.	218	0.230		
29.	217	0.230		
30.	216	0.220		
31.	229/2/2	0.500		
32.	229/2/1	0.180		
33.	229/3	0.680		
34.	228	0.110		
35.	227	0.100		
36.	226	0.100		
37.	225	0.780		
38.	224	0.390		
39.	223	0.400		
40.	215	0.340		
41.	214	0.300		
42.	213	0.310		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.	208	0.290	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
44.	207	0.180	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
45.	206	0.110	उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
46.	205	0.290		विस्तारीकरण हेतु.
47.	204/2/2	0.330		
48.	204/2/1	0.330		
49.	204/1	0.340		
50.	209	0.290		
51.	210	0.300		
52.	211/2	0.110		
53.	211/1	0.110		
54.	212/1/3	0.410		
55.	212/1/2	0.410		
56.	212/1/1	0.420		
57.	212/4	0.410		
58.	258	0.870		
59.	259/1	0.590		
60.	259/2	0.100		
61.	261/1	0.100		
62.	261/2	0.140		
63.	279/1	0.220		
64.	279/2	0.680		
65.	279/3	0.200		
66.	280/1	1.700		
67.	280/2	0.400		
68.	281	1.900		
69.	282/1	0.470		
70.	282/2	0.800		
71.	282/3	0.800		
72.	283	0.940		
73.	284	0.460		
74.	285	0.460		
75.	286	0.470		
76.	287	0.520		
77.	288/1	0.840		
78.	288/2	0.360		
79.	288/3	0.650		
80.	289	1.870		
81.	290/1	0.620		
82.	290/2	0.600		
83.	290/3	0.200		
84.	295/1	0.190		
85.	295/2	0.700		
86.	295/3	0.840		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
87.	260	0.240	कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.	औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
		<u>कुल रकबा . . 46.760</u>		

- (2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7376-रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.	38.91 हे.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण :-

(क) जिला	-	उज्जैन
(ख) तहसील	-	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	-	कड़छा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	-	39.91 हे.

क्र.	सर्वे नंबर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)		
1.	452	2.700	कार्यपालन यंत्री	औद्योगिक क्षेत्र
2.	453	0.740	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	460/1	0.750	उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
4.	460/2	0.090		विस्तारीकरण हेतु.
5.	460/3	0.040		
6.	461	0.410		
7.	462	0.600		
8.	463	0.600		
9.	464	1.520		
10.	465	0.570		
11.	466	0.900		
12.	467/1	1.420		
13.	467/2	2.700		
14.	468	2.500		
15.	469	0.870		
16.	470	4.200		
17.	471	2.540		
18.	472	0.590		
19.	473	1.450		
20.	474	0.470		
21.	475	0.240		
22.	476	0.350		
23.	477	0.300		
24.	478	0.610		
25.	479	0.790		
26.	480/1	0.710		
27.	480/2	0.750		
28.	480/3	0.750		
29.	481/1	1.640		
30.	481/2	1.100		
31.	482	4.040		
32.	431/1	0.490		
33.	431/2	0.480		
34.	441/1	0.190		
35.	441/2	0.180		
36.	459	0.630		
		<u>कुल रकबा . . . 38.91</u>		

- (2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7377-रा.प्र.क्र. 0006-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.	231.078 हे.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण :-

(क) जिला	-	उज्जैन
(ख) तहसील	-	उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम	-	नरवर
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	-	231.078 हेक्टेयर.

क्र.	सर्वे नंबर	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	55	0.250	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
2.	57	0.420	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
3.	61	1.320	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
4.	62	1.340		विस्तारीकरण हेतु.
5.	64	1.510		
6.	65	1.710		
7.	66	2.950		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	68	1.120	कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
9.	70	1.400		
10.	71	0.820		
11.	72	1.130		
12.	73/1	0.820		
13.	73/2	0.600		
14.	78	2.150		
15.	488	1.130		
16.	490	1.120		
17.	508	0.610		
18.	509	0.180		
19.	510	0.180		
20.	511	0.790		
21.	512	0.630		
22.	513	0.700		
23.	515	1.260		
24.	521	2.790		
25.	523	2.270		
26.	489/1	0.980		
27.	489/2	0.200		
28.	491/1	1.120		
29.	491/2	0.030		
30.	491/3	0.010		
31.	507/1	0.410		
32.	507/2	0.200		
33.	514/1	0.400		
34.	514/2	0.270		
35.	516/1	2.620		
36.	516/2	0.970		
37.	516/3	0.770		
38.	517/1	0.720		
39.	517/2	1.690		
40.	518/1	1.980		
41.	518/2	1.980		
42.	518/3	1.960		
43.	52/1	0.380		
44.	52/2	0.380		
45.	520/1	0.140		
46.	520/2	0.150		
47.	520/3	0.150		
48.	520/4	0.150		
49.	522/1	0.930		
50.	522/2	0.920		
51.	53/1	0.830		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52.	53/2/1	0.420	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
53.	53/2/2	0.420	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
54.	53/3	0.840	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
55.	53/4	0.830		विस्तारीकरण हेतु.
56.	54/1	1.000		
57.	54/2	1.000		
58.	59/1	1.480		
59.	59/2	1.480		
60.	59/3	1.480		
61.	59/4	1.480		
62.	60/1	1.400		
63.	60/2	0.080		
64.	65/1920	1.540		
65.	68/1930	0.840		
66.	69/1	0.520		
67.	69/2	1.000		
68.	41/1	0.260		
69.	41/2	0.360		
70.	42/1	1.090		
71.	43	1.120		
72.	44/1	0.660		
73.	44/2	0.290		
74.	44/3	0.640		
75.	45/1/1/1	0.400		
76.	45/1/1/2	0.200		
77.	45/2/2	0.080		
78.	45/2/3	0.210		
79.	46/1	0.200		
80.	47/1/1	0.100		
81.	47/1/2	0.350		
82.	47/2	0.100		
83.	47/3	0.420		
84.	48/1	0.580		
85.	48/2	0.260		
86.	48/3	0.170		
87.	49	2.090		
88.	77/1	0.520		
89.	77/2	0.200		
90.	80/1/1	0.410		
91.	80/1/2	0.130		
92.	80/1/3	0.090		
93.	80/2	0.600		
94.	81/1	1.040		
95.	81/2/1	0.953		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96.	81/2/2	0.465	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
97.	81/3	1.020	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
98.	81/4	1.020	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
99.	288/1	0.520		विस्तारीकरण हेतु.
100.	288/2	0.520		
101.	228/1	1.000		
102.	228/2	0.880		
103.	229/1	2.000		
104.	229/2/1	0.640		
105.	229/2/2	0.100		
106.	229/3	0.740		
107.	230/1	1.050		
108.	230/2	0.550		
109.	230/3	0.500		
110.	230/4	1.050		
111.	230/5	0.640		
112.	230/6	0.400		
113.	231	0.830		
114.	232/1	0.960		
115.	232/2/1	0.300		
116.	232/2/2	0.300		
117.	233/1/1	0.290		
118.	233/1/2	0.330		
119.	233/2	0.200		
120.	233/3	0.400		
121.	234	1.470		
122.	235/1	0.520		
123.	235/2	0.530		
124.	236	1.040		
125.	237	0.830		
126.	238/1	0.400		
127.	238/2	0.810		
128.	239/1/1	0.270		
129.	239/1/2	0.730		
130.	239/2	0.360		
131.	240	0.110		
132.	241/1	0.520		
133.	241/2	0.520		
134.	242	0.650		
135.	243/1	0.920		
136.	243/2	0.500		
137.	243/3	0.260		
138.	244/1	0.980		
139.	244/2	0.980		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
140.	245	1.970	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
141.	246 / 1	0.780	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
142.	246 / 2 / 1	0.520	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
143.	246 / 2 / 2	0.480		विस्तारीकरण हेतु.
144.	247 / 1 / 1	0.350		
145.	247 / 1 / 2	0.290		
146.	247 / 2 / 2	0.650		
147.	247 / 2 / 3	0.310		
148.	247 / 4	0.050		
149.	248 / 1 / 2	0.100		
150.	248 / 1 / 3	0.140		
151.	248 / 2	0.100		
152.	248 / 4	0.020		
153.	249 / 1	0.340		
154.	249 / 2	0.310		
155.	250 / 1	0.410		
156.	250 / 2	0.370		
157.	250 / 3	0.300		
158.	251 / 1	0.400		
159.	251 / 2	0.400		
160.	252	0.800		
161.	253	0.620		
162.	254	0.620		
163.	255	0.800		
164.	256	0.780		
165.	257	0.790		
166.	258	0.790		
167.	259	1.920		
168.	260	1.920		
169.	261	4.840		
170.	262 / 1	0.300		
171.	262 / 2	1.190		
172.	263	1.040		
173.	264 / 1	2.000		
174.	264 / 2	2.000		
175.	264 / 3	2.000		
176.	265	0.520		
177.	266	0.620		
178.	267 / 1	0.400		
179.	267 / 2	0.030		
180.	267 / 3	0.390		
181.	267 / 4	0.180		
182.	268	0.410		
183.	269	0.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184.	270	0.210	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
185.	271	0.420	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
186.	272	0.420	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
187.	273	0.820		विस्तारीकरण हेतु.
188.	274	0.630		
189.	275 / 1	0.580		
190.	275 / 2	1.210		
191.	276 / 1	0.170		
192.	276 / 2	1.270		
193.	276 / 3	0.470		
194.	277 / 1	1.090		
195.	277 / 2	0.520		
196.	278	0.450		
197.	279 / 1	0.380		
198.	279 / 2	0.280		
199.	280	0.880		
200.	283 / 1	0.850		
201.	283 / 2	2.340		
202.	283 / 3	0.520		
203.	284 / 1	0.510		
204.	284 / 2	1.050		
205.	284 / 3	0.260		
206.	287 / 1	1.290		
207.	287 / 2	0.490		
208.	289	1.040		
209.	347	0.320		
210.	348	0.360		
211.	349	0.630		
212.	350	0.350		
213.	351	0.970		
214.	352 / 1	0.200		
215.	352 / 1 / 2	0.080		
216.	352 / 2	0.400		
217.	353 / 1 / 1	0.180		
218.	353 / 1 / 2 / 1	0.020		
219.	353 / 1 / 2 / 2	0.030		
220.	353 / 1 / 2 / 3	0.030		
221.	353 / 2 / 1	0.110		
222.	353 / 2 / 2	0.170		
223.	353 / 2 / 3	0.170		
224.	354 / 1	0.420		
225.	354 / 2 / 1	0.240		
226.	354 / 2 / 2 / 1	0.060		
227.	354 / 2 / 2 / 2	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
228.	354/2/2/3	0.020	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
229.	354/3/1	0.160	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
230.	354/3/2	0.150	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
231.	354/3/3	0.050		विस्तारीकरण हेतु.
232.	356	1.820		
233.	357/1	0.250		
234.	357/2	0.510		
235.	358/1	0.210		
236.	358/2	0.210		
237.	358/3	0.210		
238.	358/4/1	0.750		
239.	358/4/2	0.470		
240.	359/1	0.940		
241.	359/2	0.740		
242.	360	1.660		
243.	361/1	0.200		
244.	361/2	0.200		
245.	361/3/1	0.310		
246.	361/3/2	0.520		
247.	361/4	0.830		
248.	361/5/1	0.150		
249.	361/5/2	0.250		
250.	362/1	0.430		
251.	362/2	0.710		
252.	363/1	0.970		
253.	363/2	0.970		
254.	364	0.960		
255.	365	0.900		
256.	366	1.130		
257.	367	0.970		
258.	368/1	0.660		
259.	368/2	0.330		
260.	369	0.850		
261.	370	1.130		
262.	371/1	1.100		
263.	371/2	0.440		
264.	371/3	0.400		
265.	372	0.150		
266.	373	0.180		
267.	374	0.280		
268.	375	0.200		
269.	376	0.200		
270.	377	0.200		
271.	380/1	0.610		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
272.	380/2	0.620	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
273.	380/3	0.170	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
274.	381/1	0.300	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
275.	381/2	0.480		विस्तारीकरण हेतु.
276.	381/3	0.380		
277.	381/4	0.040		
278.	382/1	0.580		
279.	382/2	0.620		
280.	383/1	0.920		
281.	463/1	0.150		
282.	463/2	0.200		
283.	463/3	1.400		
284.	464	1.750		
285.	473/1	0.030		
286.	473/2	0.030		
287.	474	1.470		
288.	475	0.530		
289.	476	1.190		
290.	477	0.080		
291.	478	0.080		
292.	479/1	0.220		
293.	479/2	0.040		
294.	480	0.080		
295.	481	0.350		
296.	482/1	0.690		
297.	482/2	0.380		
298.	482/3	0.170		
299.	483/1	0.300		
300.	483/2	0.420		
301.	483/3	0.130		
302.	484	0.400		
303.	485	2.600		
304.	496	0.580		
305.	497/1	0.140		
306.	497/2	0.140		
307.	497/3	0.140		
308.	498/1	0.920		
309.	498/2	0.140		
310.	498/3	0.140		
311.	499	0.140		
312.	500	0.170		
313.	501	1.250		
314.	520/1	0.270		
315.	502/2	1.120		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
316.	502/3	0.170	कार्यपालन यंत्री,	औद्योगिक क्षेत्र
317.	502/4	0.500	डीएमआईसी विक्रम	डीएमआईसी विक्रम
318.	503/1	0.100	उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.	उद्योगपुरी लि. के
319.	503/2	0.200		विस्तारीकरण हेतु.
320.	503/3	1.490		
321.	504/1	0.090		
322.	504/2	1.190		
323.	549/1/1	0.690		
324.	549/1/2	0.400		
325.	549/2	0.020		
326.	549/3	0.180		
327.	560/1	0.020		
328.	560/2	1.090		
329.	560/3	0.180		
330.	561/1	0.360		
331.	561/2	0.180		
332.	561/3	0.360		
333.	562	1.140		
334.	563	0.620		
335.	565/1	0.380		
336.	565/2	0.380		
337.	566	1.050		
338.	540	0.780		
339.	547/1	0.550		
340.	547/2	0.200		
341.	547/3	0.200		
342.	548	1.020		
343.	550/1	0.270		
344.	550/2	0.270		
345.	564/1	0.210		
346.	564/2	0.210		
347.	505/1	0.420		
348.	505/2	0.530		
349.	505/3	0.930		
350.	290	1.250		
351.	291	1.300		
352.	355/1	0.260		
353.	355/2	1.200		

कुल रकबा . . 231.078

- (2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-137-भू-अर्जन-24

मैहर, दिनांक 3 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - उफरी

(घ) क्षेत्रफल- 2.7350.हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	35/1	0.0020
2	26	0.0420
3	55	0.0010
4	57	0.0070
5	50/2	0.0030
6	118	0.0060
7	110	0.0040
8	109	0.1050
9	102	0.0040
10	96/2	0.2000
11	101/2	0.0040
12	89/4	0.0110
13	114/1	0.0180
14	114/2	0.0180
15	114/3	0.0180
16	114/4	0.0060
17	27/1	0.0520
18	74	0.0140
19	117	0.0040
20	85/1	0.1850
21	85/4	0.0210
22	85/5	0.0310
23	90	0.0020
24	91/1	0.1940
25	91/2	0.1940
26	92/1	0.0450
27	92/2	0.1020
28	49/1	0.0670
29	49/2/1/2	0.0210
30	49/2/2	0.0730
31	49/2/3	0.0370
32	56	0.0600
33	25	0.0020
34	78/1	0.0280
35	78/2/1	0.0660
36	78/2/3	0.0580
37	78/3	0.0810
38	79/1	0.0580
39	87/2	0.2090
40	87/3	0.2090
41	87/4	0.0160
42	88/1	0.0040
43	88/3	0.0130
44	88/4	0.1540
45	29	0.0320
46	47	0.1570
47	48	0.0010
48	28/2	0.0030
49	80/1	0.0490
50	95	0.0600
	योग	2.7350

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की जरमोहरा माइनर एवं भटिगावां माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-148-भू-अर्जन-24

मैहर, दिनांक 20 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम -ककरा

(घ) क्षेत्रफल- 6.220 हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकबा
1	2	3
1	414/1	0.0160
2	414/2	0.0180
3	414/3	0.0900
4	413/1	0.1750
5	459/1	0.1260
6	459/2	0.0620
7	458/2	0.1260
8	457/2	0.0570
9	457/4	0.0580
10	456	0.1600
11	462/1	0.0410
12	462/2	0.0110
13	463/1	0.1450
14	464	0.0800
15	470	0.0010
16	473/1	0.0200
17	473/2	0.0610
18	472/1/1/1	0.0540
19	472/1/1/2	0.0460
20	472/1/2	0.0700
21	472/2	0.0380
22	471/1	0.0040
23	471/2	0.0410
24	477/1/1	0.0220
25	477/1/2	0.0350
26	477/1/3	0.0420
27	477/1/4	0.1080
28	477/2	0.0860
29	476/3	0.0160
30	485	0.0890
31	496	0.0920

32	487	0.0570
33	486	0.0330
34	489/1	0.0190
35	561	0.0460
36	560/2	0.0330
37	567/1	0.0120
38	567/2	
39	568/1	0.0100
40	568/2	
41	569/1	0.0380
42	569/2	0.0890
43	570	0.0780
44	571/1	0.0260
45	571/2	
46	555	0.0420
47	557	0.0020
48	556	0.0300
49	572	0.0050
50	553	0.0180
51	554/1	0.0030
52	554/2	0.0420
53	554/3	0.0490
54	551	0.0370
55	550/1	0.0830
56	550/2	
57	549/1	0.0470
58	549/2	0.0110
59	526/3	0.0480
60	547	0.1700
61	546/1/1	0.1430
62	546/1/2	
63	546/2	
64	545/1	0.1290
65	545/2	
66	545/3	
67	583/1	0.0760
68	5832	
69	5833	
70	584/2	0.0100
71	584/3	0.0310
72	1005/1	0.0400
73	1004	0.1320
74	1001/1	0.0350
75	1001/2	0.0300
76	1000/1	0.0090
77	1000/2	0.0810
78	1002/1	0.0140
79	1002/2	

80	1002/3	
81	998/3	0.0300
82	997/2	0.0650
83	996/1	
84	996/2	
85	996/2/3	0.0630
86	996/3/1	
87	996/3/2	
88	982/2	0.0740
89	980/1	0.0120
90	983	0.0380
91	1125	0.0650
92	1128	0.0730
93	1130/1/1	
94	1130/1/2	0.0100
95	1130/2	
96	1127	0.0010
97	1133	0.0920
98	1136/1	0.0630
99	1136/2/2	0.0040
100	1137/2	0.0960
101	1157/1/1	
102	1157/1/2	0.0870
103	1157/1/3	
104	1157/2	0.0840
105	1157/3/1	0.0250
106	1157/3/2	0.0260
107	1157/4	0.0330
108	1158/1	0.0610
109	1158/2	0.0100
110	1159	0.0520
111	1160/2	0.1310
112	1161/2	0.0060
113	1175/1	
114	1175/2	0.0620
115	1176/1/1	0.0040
116	1177/1/1	0.0050
117	1178/1	0.1150
118	1178/2	0.0930
119	1180/1	0.0020
120	1180/2	0.0440
121	1180/3	0.0120
122	1179/1	0.0120
123	1179/2	0.0120
124	1179/3	0.0120
125	1179/4	0.0130
126	920	0.0200
127	925/5	0.0660
128	924/5	0.0090
129	922	0.0250
130	923/1	0.1180
131	923/2	0.0180
132	915	0.1930
133	914	0.0960
134	913	0.0660
135	911	0.0890
136	899/2	0.0120
137	910	0.0610
138	900/1	
139	900/2	
140	900/3	0.1120
141	900/4	
	योग	6.220

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बजैनाथ उपशाखा की मौहट माइनर नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-149-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम -भीष्मपुर
(घ) क्षेत्रफल- 3.594हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	705/1	0.0290
2	705/2/2	0.0290
3	705/3	0.0320
4	705/2/1	
5	705/4	
6	700	0.0310
7	701/1	0.0160
8	701/5	0.0550
9	699	0.0070
10	696	0.0470
11	695	0.0090
12	692/1	0.0630
13	693/2	0.0500
14	690/1/3/2	0.0120
15	690/2	0.0530
16	684/1/2	0.0580
17	684/1/3	0.0070
18	684/2/1	0.0170
19	684/2/2	0.2110
20	685/1/1	0.0110
21	685/1/2	0.0110
22	686/2	0.1040
23	686/3	
24	624	0.1050
25	625/1	0.0140
26	626/2	0.0970
27	693/1	0.0080
28	627/1	0.0940
29	640/1/1/1	0.0210

30	640/2	0.0670
31	664/1	0.0690
32	664/2	0.0970
33	663/1	0.0320
34	645	0.0760
35	646/1	0.0790
36	650	0.0970
37	649/1/2	0.0690
38	649/2	0.0700
39	407	0.0370
40	406	0.2190
41	410	0.2180
42	411	0.0790
43	412	0.1890
44	641/2	0.0130
45	405/1	0.0130
46	405/2	0.0120
47	275/1	0.0840
48	277	0.0500
49	278	0.0420
50	279	0.0300
51	280	0.0300
52	282	0.0430
53	281	0.0010
54	290	0.0060
55	291	0.0040
56	293/2	0.0490
57	295	0.0010
58	294	0.0510
59	300	0.0470
60	325	0.0180
61	347/1	0.0120
62	347/2	0.0070
63	347/3	0.1520
64	335/1	0.0100
65	346	0.0060
66	336/1	0.0810
67	336/2	0.0820
68	337	0.0110
69	338	0.0280
70	331	0.0710
71	339	0.0510
योग		3.5940

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के किंगरा वीरदत्त माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-150-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम -ककरा

(घ) क्षेत्रफल-0.843हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	983	0.089
2	985	0.041
3	1125	0.002
4	989	0.068
5	991	0.181
6	992	0.040
7	1111	0.154
8	1107/1	0.031
9	1107/2/1	0.083
10	1107/2/2	0.075
11	1107/3	0.071
12	1102/1/1	0.008
	योग	0.843

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-151-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
 (ख) तहसील-अमरपाटन
 (ग) नगर /ग्राम -किरहाई
 (घ) क्षेत्रफल- 1.174 हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	28	0.305
2	25	0.086
3	26	0.014
4	23	0.036
5	22	0.035
6	14	0.021
7	13	0.009
8	2	0.244
9	3	0.058
10	1	0.089
11	4/1/1	0.049
12	4/1/2	0.008
13	5/1/1/1	0.160
14	5/1/1/4	0.025
15	5/1/2	0.035
	योग	1.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-152-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम -ओवरा

(घ) क्षेत्रफल- 3.7090हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	479	0.0530
2	442/1	0.0080
3	442/2	0.0070
4	442/3	0.0080
5	443/1	0.0510
6	443/2	0.0030
7	477/4	0.1130
8	477/1/1	0.0430
9	477/1/2	0.0430
10	477/2	0.0840
11	466	0.0110
12	510	0.0350
13	509	0.0530
14	508/1	0.0090
15	508/2/1	0.0010
16	508/2/2	
17	508/2/3	
18	508/3/1/1	0.0300
19	508/3/1/2	0.0300
20	508/3/2	0.0170
21	507/1	0.0020
22	507/2/1	0.0010
23	507/2/2	0.0010
24	507/2/3	0.0010
25	507/3/1	0.0020
26	507/3/2	0.0020
27	520/1	0.0300
28	520/2	
29	521/1	0.2000
30	521/2	
31	522/1	0.0100
32	522/2	
33	345	0.1510

34	346	0.0070
35	339	0.0080
36	336/1	0.0030
37	336/2	0.0040
38	337/1	0.0230
39	337/2	0.0230
40	335	0.0410
41	333	0.0520
42	330	0.0090
43	328/1	0.1410
44	328/2/1	0.0050
45	328/2/2	
46	328/2/3	
47	327/1	0.0020
48	327/2	0.0020
49	325/1	0.0100
50	325/2	
51	325/3	
52	326/1	0.0110
53	326/2	
54	326/3	
55	281/1/1	0.0710
56	281/1/2	0.0250
57	281/2	0.0100
58	282/1	0.0140
59	308/1	0.0800
60	308/2	
61	308/3	
62	307/1	0.0140
63	291	0.0560
64	292	0.0900
65	293	0.0100
66	306	0.0620
67	305	0.0400
68	299/1	0.0030
69	299/2	
70	304/1	0.0180
71	304/2	0.0180
72	302/1/1/1	0.0280
73	302/1/1/2	0.0450
74	302/1/2	0.0440
75	302/2	0.0860
76	303/1	0.0015
77	303/2	0.0015
78	216	0.0120
79	217	0.0130
80	215	0.0780
81	99/1	0.0680
82	196	0.0900
83	195	0.0030
84	129	0.0100
85	127	0.0010
86	126	0.0040
87	130	0.1000

88	134/1	
89	134/2	0.0840
90	134/3	
91	125/1	0.0020
92	135/1	0.0070
93	135/2	
94	135/3	
95	136/2	0.1380
96	137	0.0120
97	138/1/2	0.0620
98	120/1/2/2	0.0220
99	119/1/2	0.0380
100	139/1/1/2	
101	139/1/2	0.0480
102	139/2	
103	140	0.0390
104	141	0.0040
105	42	0.0690
106	118/1/2	0.0130
107	43/1	0.1330
108	44/1	0.0060
109	46	0.0340
110	45	0.0940
111	15	0.0940
112	14	0.0140
113	13/1	0.0510
114	13/2	0.0510
115	12/1	0.0150
116	12/2	0.0140
117	6/1	
118	6/2	0.1240
119	5	0.1050
	योग	3.7090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका की तिघरा माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-153-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम -इटमा कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 4.890हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकबा
1	2	3
1	14	0.200
2	15/1	0.005
3	16/1	0.099
4	17/1	0.108
5	17/2	0.011
6	18/1	0.002
7	18/2	0.003
8	29/1/1	0.250
9	29/1/2	0.032
10	29/2	0.018
11	31/1	0.029
12	31/2	0.001
13	31/907	0.192
14	43	0.145
15	44	0.043
16	45/1	0.072
17	45/2	0.058
18	54/2	0.005
19	49/1	0.016
20	49/2	0.054
21	47/1	0.023
22	47/2	0.016
23	50	0.008
24	152/1	0.003
25	134	0.131
26	132	0.001
27	133	0.092
28	135	0.048
29	136/1	0.040
30	136/2	0.128

31	128/1	0.007
32	128/2	0.077
33	127	0.160
34	126	0.112
35	125	0.122
36	124	0.043
37	119	0.295
38	217	0.069
39	218	0.083
40	240	0.408
41	238/1	0.124
42	238/2	0.064
43	238/3	0.008
44	247	0.105
45	248/1	0.277
46	248/2	0.075
47	246	0.012
48	251	0.199
49	250	0.282
50	252/2/2	0.003
51	301	0.219
52	302	0.033
53	296	0.180
54	295	0.013
55	293	0.087
	योग	4.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-157-भू-अर्जन-24

मैहर, दिनांक 30 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम - करसरा
(घ) क्षेत्रफल- 2.8470.हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	1/1/1/1	0.0300
2	1/2/1	0.0300
3	2/1/1	0.1580
4	2/1/2	0.0730
5	2/2/1/1/1	0.0670
6	2/2/1/1/2	0.0170
7	2/2/1/2	0.1580
8	2/2/2/3	0.0260
9	188	0.0020
10	532	0.0300
11	534	0.0060
12	543	0.1350
13	541	0.0010
14	539	0.0490
15	315	0.0020
16	331	0.0040
17	329	0.0020
18	189	0.0120
19	190	0.0320
20	242	0.0250
21	243/2	0.6860
22	243/1	0.1340
23	289	0.0040
24	290	0.0450
25	291	0.0040
26	297	0.0140
27	298	0.0040
28	299	0.0020
29	326	0.0300
30	327	0.0330
31	328	0.0580
32	241	0.0450
33	154	0.0030
34	200	0.0090
35	201	0.0060
36	202	0.0190

37	203	0.0020
38	204	0.0160
39	205	0.0010
40	206	0.0160
41	207	0.0160
42	208/1	0.0660
43	208/2	0.0840
44	208/4	0.0320
45	211	0.0160
46	212	0.0310
47	214/2	0.0030
48	239	0.0310
49	415	0.0470
50	416	0.0150
51	417/1	0.0220
52	417/2	0.0080
53	417/3	0.0880
54	421/1	0.0500
55	446/1	0.0120
56	446/2	0.0200
57	447	0.0310
58	448/1	0.0120
59	452	0.1420
60	523	0.0250
61	524	0.0640
62	525	0.0060
63	527	0.0120
64	528	0.0960
65	529	0.0120
66	530	0.0310
67	536	0.0830
68	295	0.0210
69	240	0.0020
70	296	0.0200
	योग	2.8470

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत जरमोहरा वितरिका की मगरौरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-158-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम -मगराज
(घ) क्षेत्रफल- 1.715 हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकबा
1	2	3
1	712	0.042
2	711/1/1/1	0.028
3	715	0.168
4	719/1/1/1	0.003
5	716/1	0.026
6	716/2	0.028
7	716/3	0.041
8	716/4/1	0.004
9	716/4/2	0.006
10	717/1	0.090
11	717/2	0.013
12	718	0.016
13	754	0.101
14	753/1	0.022
15	753/2	0.067
16	752	0.058
17	751/2	0.005
18	750	0.098
19	757/2	0.005
20	748	0.069
21	749/1	0.008
22	749/2	0.014
23	749/3	0.032
24	733/1	0.040
25	733/2/2	0.070
26	733/2/1	0.155
27	732	0.075
28	645/1	0.427
29	735	0.004
	योग	1.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-159-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम -परसवाही

(घ) क्षेत्रफल- 2.990 हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकबा
1	2	3
1	409/3	0.011
2	456/1	0.070
3	456/2	0.024
4	456/3	0.070
5	455	0.021
6	461/1	0.166
7	461/2/2	0.070
8	463	0.079
9	492/1	0.058
10	492/2	0.030
11	492/3	0.047
12	491/1	0.020
13	491/2/1	0.097
14	490	0.030
15	580/1/1	0.040
16	580/1/2	0.066
17	580/1/3	0.056
18	580/1/4	0.014
19	580/2	0.021
20	580/4	0.088
21	581/2	0.007
22	581/3	0.007
23	583/3	0.005
24	462/1	0.002
25	462/2	0.144
26	584/1/1	0.045
27	584/1/2	0.055
28	584/1/3	0.040
29	584/1/4	0.050

30	791	0.299
31	803	0.012
32	781/1	0.166
33	781/2	0.128
34	781/894	0.062
35	781/893/4	0.063
36	781/892/2	0.034
37	775/4	0.052
38	774	0.073
39	773	0.116
40	771	0.159
41	852	0.010
42	853/1	0.183
43	853/2	0.165
44	853/3/2	0.001
45	854/1	0.012
46	585	0.022
	योग	2.990

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की वीरदत्त माइनर नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-160-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम -नौगवों
(घ) क्षेत्रफल- 2.594 हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकबा
1	2	3
1	577/954	0.060
2	599	0.108
3	598/1	0.048
4	598/2	0.040
5	603/3	0.004
6	603/4	0.024
7	603/5	0.024
8	597/2	0.029
9	604	0.118
10	620/1	0.159
11	627/943/2	0.028
12	627	0.052
13	626	0.066
14	628	0.104
15	596/2	0.017
16	629/1	0.537
17	800/1	0.010
18	800/2	0.144
19	799/1	0.053
20	799/2	0.040
21	799/3	0.030
22	794/1/1/1	0.001
23	793/1/1/1/1/1	0.164
24	793/1/1/1/3	0.164
25	793/1/2/1	0.016
26	793/2	0.180
27	793/5	0.180
28	787/1	0.194
	योग	2.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-161-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम -चोरखंडी

(घ) क्षेत्रफल- 2.692 हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	757/1/1/1	0.133
2	757/1/2/1	0.026
3	756/1	0.011
4	725/1	0.156
5	726/1	0.084
6	742/1	0.020
7	742/2	0.039
8	741	0.047
9	740/2	0.019
10	729	0.043
11	730/1	0.031
12	730/2	0.030
13	731	0.046
14	733	0.051
15	734	0.065
16	664/5	0.064
17	664/6	0.066
18	661/1	0.008
19	661/2/1	
20	661/2/2	
21	661/3	
22	661/4	
23	661/5	
24	659/1	0.017
25	659/2	0.123
26	658/2	0.011
27	622/1	0.036
28	622/2	0.019
29	622/3	0.022

30	622/4	0.012
31	622/5	0.012
32	622/6	0.012
33	622/7	0.013
34	625/3	0.011
35	626/2	0.095
36	626/3	0.114
37	626/4	0.093
38	626/5	0.096
39	626/6	0.070
40	626/7	0.096
41	626/8	0.021
42	627/1	0.020
43	609/2/1	0.008
44	608/1/1/1/1	0.194
45	608/1/1/1/2	
46	608/1/2	
47	608/2	0.045
48	607/1/1/1/1	0.015
49	607/1/1/1/2	
50	607/1/2	
51	584/1	0.009
52	586/1	0.081
53	586/2	0.092
54	585/1	0.019
55	587/2	0.016
56	588/4/1/2	0.030
57	588/4/2	0.090
58	588/5	0.068
59	589/4/1/2	0.020
60	589/4/2	0.010
61	596	0.154
62	593	0.009
	योग	2.692

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-162-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
 (ख) तहसील-अमरपाटन
 (ग) नगर /ग्राम -मझगवां
 (घ) क्षेत्रफल- 4.252 हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकबा
1	2	3
1	190	0.003
2	191	0.006
3	195/1	0.164
4	195/2	0.01
5	196/1065	0.210
6	196	0.089
7	198	0.010
8	199/1	0.078
9	199/2	
10	200/1	0.160
11	200/2	
12	200/3/1	
13	200/3/2	
14	200/4	0.011
15	201/1	
16	201/2	
17	201/3/1	
18	201/3/2	
19	201/4	0.059
20	206	
21	205	0.109
22	281	0.047
23	280	0.030
24	279	0.008
25	283	0.153
26	272/1	0.060
27	272/2	0.005
28	271/1	0.022
29	271/2	0.033

30	267	0.071
31	266	0.111
32	263	0.162
33	294/1	0.023
34	294/2	0.002
35	260	0.191
36	259/3	0.020
37	255/1	0.100
38	255/2	0.046
39	254/2	0.191
40	899	0.051
41	310/1	0.127
42	892/4/1	0.028
43	890/2	0.128
44	889/2	0.005
45	312	0.131
46	888	0.052
47	887	0.030
48	952/2	0.072
49	885/1	0.004
50	953	0.155
51	960	0.091
52	961	0.066
53	958/1/1	0.024
54	962/1	0.013
55	962/2	0.013
56	964/2	0.238
57	965/2	0.007
58	963/1	0.010
59	963/2	0.010
60	966/1	0.058
61	1002/1	0.011
62	1002/2	0.043
63	1003	0.129
64	752/2	0.002
65	752/3	0.020
66	1005/1	0.062
67	1005/2	0.024
68	1008/1/2	0.033
69	1008/2	0.034
70	1007/1/1	0.004
71	1007/1/2	0.006
72	1007/2	0.002
73	1009	0.016
74	746/1	0.009
75	746/2	0.035
76	1038/1/1	0.058
77	1038/1/2	0.058
78	1038/2	0.058

79	1039/1	0.258
80	1039/2	
81	1035/1	0.003
82	1035/1/1	
83	1035/1/3	
84	1035/1/4	
85	1035/1/5	
86	1035/1/8	
87	1035/1/9	
88	1035/1/16	
89	1035/2	
90	1040/1	
91	1040/1/1	
92	1040/1/3	
93	1040/1/4	
94	1040/1/5	
95	1040/1/6	
96	1040/1/9	
97	1040/1/12	
98	1040/1/16	
99	1040/1/27	
100	1040/2	
101	1010/2	0.010
	योग	4.252

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-163-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
 (ख) तहसील- मैहर
 (ग) नगर /ग्राम - करूआ
 (घ) क्षेत्रफल- 4.3980हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	1134	0.0020
2	1136	0.0110
3	1147/2/1	0.1610
4	1155/1/2/1	0.0820
5	1155/1/2/2	0.0110
6	1155/2	0.2090
7	1156	0.0670
8	449	0.0010
9	437/1/2	0.1860
10	437/2	0.0050
11	1441	0.0720
12	1444	0.0110
13	830	0.0250
14	829	0.0370
15	835	0.0250
16	903/1	0.0480
17	904	0.0210
18	836	0.0220
19	837	0.0190
20	916	0.0370
21	915	0.0260
22	901	0.0310
23	900	0.0250
24	899	0.0260
25	884	0.0250
26	883	0.0090
27	880	0.0050
28	885	0.0460
29	886	0.0260
30	887	0.0110
31	878	0.0100

32	877	0.0310
33	864	0.0040
34	438/2	0.0070
35	450	0.0680
36	451	0.1140
37	454/2	0.0140
38	484	0.0240
39	485	0.0260
40	486	0.0260
41	487/1	0.0350
42	487/2	0.0350
43	493/1	0.0200
44	493/2	0.0200
45	493/3	0.0200
46	496	0.0790
47	497	0.0010
48	609/1	0.0880
49	609/2/1	0.0270
50	609/2/2	0.0070
51	609/4	0.0650
52	636/1	0.1650
53	644/2	0.0230
54	645	0.1920
55	646/2	0.0200
56	647/1/1	0.1850
57	647/2/1	0.0870
58	647/2/2	0.0910
59	838	0.0040
60	839	0.0200
61	842	0.0130
62	845	0.0130
63	847	0.0110
64	855	0.0020
65	856	0.0020
66	857	0.0030
67	858/2	0.0040
68	1128/2/3	0.0910
69	1128/2/4	0.0240
70	1128/2/6	0.1230
71	1151/2	0.0720
72	1154/1	0.1480
73	1473	0.0260
74	1475/2	0.2510
75	1517	0.0020
76	1518	0.0010
77	1519	0.0150
78	1520	0.0510
79	1521	0.0070
80	1522	0.0580

81	1525	0.0080
82	1524	0.0210
83	1446	0.0610
84	637	0.0700
85	1157/2/2	0.0110
86	1157/3/1	0.0630
87	1157/3/2/1	0.0350
88	1532	0.0130
89	1155/1/2/1	0.0820
90	1155/1/2/2	0.0110
91	1155/2	0.2090
92	449	0.0010
93	1443	0.0310
94	1437/1/1	0.0060
95	1439	0.0590
96	1438	0.0010
97	897	0.0010
98	861/2/2	0.0010
99	636/2/1	0.0070
	योग	4.3980

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की अंतर्गत जरमोहरा वितरिका की करुआ माइनर, मगरौरा सब माइनर एवं देवरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-164-भू-अर्जन-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम - जरमोहरा
(घ) क्षेत्रफल- 2.1010.हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	152	0.0100
2	146/1/1	0.0630
3	146/1/2	0.0300
4	146/3	0.0050
5	212	0.0380
6	71	0.0020
7	72	0.0450
8	73/2	0.0100
9	75/2	0.0320
10	101	0.0290
11	118	0.0020
12	119	0.0770
13	120	0.0970
14	121/1	0.0210
15	124	0.0720
16	144/2	0.0120
17	144/3	0.0120
18	144/4	0.0120
19	144/5	0.0120
20	145	0.0760
21	147	0.0740
22	150	0.3160
23	151/1	0.0670
24	151/2	0.1000
25	213	0.0480
26	214	0.1480
27	216	0.0090
28	222/2/2	0.0020
29	223	0.1290
30	254	0.0580
31	258/1/2	0.0980
32	258/2/1	0.0660
33	261/1/1	0.0650
34	261/1/2	0.0050
35	261/2/1	0.0350
36	261/2/2	0.0350
37	69/1	0.0380
38	148/1	0.0380
39	148/2	0.0100
40	123	0.0320
41	255	0.0710
	योग	2.1010

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, सीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका माइनर नहर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-165-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - नरौरा

(घ) क्षेत्रफल- 3.5990हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	109	0.0140
2	47/1/1/1/1/1/1/1	0.0420
3	108/1	0.0020
4	333/1/2	0.0010
5	332	0.0010
6	337	0.0020
7	163	0.0020
8	164/3	0.1680
9	165/3	0.0080
10	166/1	0.0080
11	166/3/1	0.0920
12	166/3/2	0.0550
13	167/1/1	0.0020
14	167/1/2	0.0010
15	167/2	0.0190
16	167/3	0.0200
17	208/1	0.0060
18	209/1	0.0020
19	210	0.0250
20	582/210	0.0230
21	211	0.0530
22	244	0.0280
23	347	0.0620
24	348	0.0490
25	216	0.0190
26	217/1	0.0280
27	217/2	0.0040
28	252/3	0.0120
29	358	0.0200
30	359/1	0.0140
31	359/2	0.0140
32	379/2/1	0.0300
33	186/1	0.0160
34	187/1/1	0.0730
35	188/1	0.0160

36	189/1/1	0.0880
37	189/2	0.1140
38	200	0.0080
39	201/1	0.2410
40	202/1	0.0080
41	341	0.0940
42	330	0.0240
43	331	0.3120
44	205	0.0070
45	206	0.0060
46	360	0.0500
47	191/2	0.0080
48	192/1/1	0.1090
49	192/2	0.0900
50	194/2	0.0060
51	301	0.0730
52	302/1	0.0200
53	302/2	0.0200
54	304	0.0320
55	306	0.0140
56	307	0.0090
57	198/3	0.0300
58	199	0.1170
59	305	0.0210
60	45/1	0.0570
61	53/1	0.1330
62	53/2	0.0420
63	52/1/2	0.1150
64	81/1/1	0.0810
65	81/1/2	
66	81/2/1/1/1	
67	81/2/1/1/2	
68	81/2/1/1/3	
69	81/2/1/1/4	
70	81/2/1/1/5	
71	81/2/1/1/6	
72	81/2/1/1/7	
73	81/2/1/1/9	
74	81/2/1/1/10	
75	81/2/1/1/11	
76	81/2/1/1/12	
77	81/2/1/1/13	
78	81/2/1/1/14	
79	81/2/1/2/1	
80	81/2/2/1	
81	81/2/2/2	
82	81/2/2/3	
83	81/2/1/2/2	
84	81/3	
85	81/4/1/1	
86	81/4/1/2	
87	81/4/1/3	
88	81/4/2	
89	106/1	

90	105/1	0.0330
91	104	0.0820
92	103	0.0090
93	102	0.0100
94	101/1	0.0020
95	101/2	
96	101/3	
97	101/4	
98	101/5	
99	101/6	
100	99/2	0.0520
101	110	0.0800
102	111/1/1/1/1/1/1/1	0.0770
103	111/2/2	0.0200
104	96/1	0.1080
105	92	0.1570
106	91	0.0210
107	93	0.0260
	योग	3.5990

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा (24 से 33 कि०मी०) के अंतर्गत नरौरा वितरिका एवं पहाड़ी माइनर के नहर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-2064-भू-अर्जन-24

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्र-एक सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :- (म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- मरु

(घ) क्षेत्रफल :- 1.4350 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.में	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	25/3	0.0840	
2	32/1	0.0110	
3	33	—	0.0140
4	34	0.0760	
5	35/2	0.0250	
6	36	—	0.0050
7	37/1	0.1320	
8	83	—	0.0190
9	88/1/1	0.0690	
10	88 /1/2/1	0.0700	
11	89/1	0.0290	
12	90	—	0.0240
13	91/1	0.0600	
14	91/2	0.0600	
15	92/2	0.0060	
16	99/1	0.0640	
17	100/2	0.0250	
18	100/3	0.0510	

19	101	0.1670	
20	102	0.0450	
21	108	0.0160	
22	110	—	0.0060
23	111/1	0.0250	
24	111/2	0.0250	
25	111/3	0.0310	
26	112	—	0.0050
27	113	0.0560	
28	114	0.0970	
29	116	—	0.0020
30	117	0.0270	
31	118	0.0540	
32	119	0.0070	
33	123 शा.नं.122 में	0.0150	
34	124 शा.नं. 122में	0.0180	
35	144	0.0050	
36	145/1	0.0100	
	योग	1.3600	0.0750
	महायोग	1.4350	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवों शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2236-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - देवार

(घ) क्षेत्रफल- 1.7050 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	2/1/1	0.0520
2	2/2/1	0.0370
3	2/3/1	0.0330
4	2/4/1	0.0430
5	3/1/1/1	0.0620
6	3/1/1/2	0.0630
7	7/1	0.1030
8	18	0.0020
9	17/1	0.0060
10	17/2	0.0080
11	10/1	0.0300
12	9	0.0610
13	16/1	0.1000
14	84	0.0300
15	83	0.0010
16	81	0.3100
17	80	
18	79	
19	78	
20	77/1	
21	77/2	

22	107	0.0310
23	106	0.0940
24	105	0.0060
25	108/1	0.0090
26	108/2	0.0060
27	109/1	0.0460
28	109/2	0.0210
29	110/1	0.0600
30	110/2	0.0320
31	111/1	0.0340
32	111/2	0.0340
33	111/3	0.0340
34	117	0.1940
35	123/1	0.0940
36	123/2	
37	123/3	
38	123/4	
39	122/1	0.0070
40	122/2	
41	122/3	
42	124/1	0.0290
43	124/2	
44	124/3	
45	125	0.0270
46	87/1/2	0.0060
		1.7050

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2221-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.- एक, सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :- सतना

(ख) तहसील :- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :- गोडगवां

(घ) क्षेत्रफल :- 0.0360 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा क्र.	निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	88/2 में शामिल नं. 89	0.0360	—
	योग	0.0360	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवां शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2237-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - घोटी
(घ) क्षेत्रफल- 2.441 हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	28/1/1	0.1050
2	28/1/2	
3	27/1	0.0700
4	41/2/1	0.2150
5	41/2/2	
6	42/2/2	0.0200
7	18/1/1/1	0.3300
8	18/1/1/2	
9	18/1/2	
10	18/1/3	
11	17/4/2	0.0150
12	16	0.1200
13	15	0.0230
14	60/1	0.1450
15	61/1	0.3450
16	62	0.0120
17	88/1/1	0.5230
18	88/2/1	
19	87/3	0.0180
20	87/2	
21	124/1	0.0450
22	124/2	
23	125/1/1	0.0240
24	125/2/2	
25	126	0.0110
26	127	0.1400
27	128	0.0300
28	85	0.0150
29	25	0.0080
30	129	0.0470
31	26	0.1050
32	43/1	0.0250
33	14/2	0.0500
	कुल योग रकबा हे.में-	2.4410

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी ब्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2239-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - पिपरीकला

(घ) क्षेत्रफल- 0.8170 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
1	2	3
1	2044/1	0.0120
2	2045/1	0.0950
3	2012/1	0.1020
4	2012/2/2	0.1030
5	2011/2/2	0.0140
6	2010/1	0.1690
7	2009/1	0.0070
8	2007/2	0.0100
9	2028/2	0.0290
10	2028/4	0.0060
11	2027/2	0.0020
12	2019/1/2	0.0800
13	2019/4	0.0850
14	2019/5	0.0850
15	2008/1	0.0180
	कुल योग रकबा हे.में-	0.8170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2240-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - सौनवर्षा

(घ) क्षेत्रफल- 2.3360 हे०

क्र.	खसरा नं.	कुल अर्जित रकवा
(1)	(2)	(3)
1	85/1	0.2650
2	84/2	0.0840
3	84/3	
4	84/4	
5	84/5	
6	87/1	0.1250
7	87/2	0.0120
8	88	
9	89/1	0.0150
10	89/2	
11	93/1	0.0100
12	93/2	
13	93/3	
14	93/4	
15	93/5	
16	94/1	0.1300
17	94/2	
18	94/3	
19	94/4	
20	95/1	0.0200
21	95/2	
22	95/3	
23	95/4	

24	118/1	0.0600
25	118/2	
26	119/1/2/1	0.4240
27	119/1/2/2	
28	119/2/1	
29	119/2/2	
30	52/1	0.1300
31	52/2	
32	57/1	0.0450
33	57/2	
34	57/3/2	
35	57/3/3	
36	57/4/1	
37	57/4/2	
38	56	0.1650
39	54/4/1	0.0460
40	54/4/3	
41	73/1	0.1600
42	73/2/1	
43	73/3	
44	75/1/1	0.2400
45	75/1/2	
46	75/1/3	
47	75/2/1	
48	75/2/2	
49	75/2/3	
50	75/3	
51	81/1	0.1100
52	81/2/1	
53	81/2/2	
54	81/2/3	
55	81/3	

56	91	0.0800
57	92/1/1	0.0200
58	92/1/2	
59	92/2	
60	92/3/1	
61	92/3/2	
62	58	0.0040
63	76/1	0.0500
64	76/2	
65	76/3	
66	76/4	
67	136/1/1	0.0620
68	136/1/2	0.0620
69	136/2/1/2	0.0020
70	66/2	0.0150
	कुल योग रकबा हे.में-	2.3360

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा. नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2241-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - पपरेगा

(घ) क्षेत्रफल- 0.6620 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	614	0.0310
2	613	0.0230
3	611	0.0060
4	610	0.0070
5	632	0.0020
6	633	0.0030
7	639	0.0130
8	638	0.0110
9	640	0.0010
10	642	0.0130
11	643	0.0310
12	644	0.0010
13	681	0.0050
14	684/2	0.0310
15	683	0.0390
16	684/1/1	0.0060
17	684/1/2	0.0050
18	685/1	0.0140
19	685/2	0.0260
20	686/1	0.0050
21	686/2	0.0110
22	688/1	0.0100
23	687/1	0.0090
24	678/2	0.0190
25	706/1	0.0420
26	706/2	0.2980
	कुल योग रकबा हे.में-	0.6620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की कुलपुरा सब माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2377-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - बिहटा

(घ) क्षेत्रफल- 9.5930 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	23/1	0.0940
2	23/2	0.0940
3	57	0.1350
4	58/1/1	0.1000
5	58/1/2	0.0820
6	59/1	0.0730
7	76/1	0.0420
8	76/3	0.0870
9	75	0.0600
10	77	0.0310
11	78	0.0360
12	79	0.1010
13	80/1	0.0030
14	80/2	0.0630
15	68	0.0300
16	81	0.0210
17	249	0.0450
18	248	0.0600
19	252/2	0.0820
20	253	0.0570
21	250	0.0650
22	251	0.0730
23	246	0.0790

24	425	0.0250
25	426	0.1600
26	245	0.0140
27	433	0.0920
28	434/1	0.1170
29	434/2	0.0420
30	441	0.0910
31	442	0.0090
32	436	0.0630
33	438	0.0410
34	427	0.0070
35	447	0.0650
36	448	0.0870
37	437	0.0690
38	524	0.1180
39	523	0.2580
40	522	0.1360
41	521	0.0420
42	520/1	0.0160
43	551	0.0730
44	552	0.0730
45	553	0.0370
46	557	0.0980
47	558	0.2200
48	559	
49	560/1	
50	560/2	
51	665/1	
52	665/2	
53	666	
54	668	0.0430
55	656	0.0060
56	663	0.0860
57	660	0.0420
58	661	0.1080

59	672	0.0300
60	657	0.0730
61	658	0.0500
62	650	0.0300
63	647/2	0.0050
64	643	0.0180
65	644	0.0660
66	649	0.1020
67	645	
68	646/1	
69	646/2	
70	635/2/1	0.0420
71	1417/1/2	0.0310
72	1417/2/1	0.1460
73	2241	0.0100
74	2242	0.0420
75	2243	0.0330
76	2248	0.0180
77	2259	0.2420
78	2258	0.0090
79	2274	0.1490
80	2277	0.1710
81	2278	0.0680
82	2280	0.0510
83	2281	0.0180
84	2282/2	0.0810
85	2284	0.0760
86	2283	0.0200
87	2286	0.0020
88	2317	0.0730
89	2326	0.0020
90	2318	0.0420
91	2319	0.0460
92	2321	0.0270
93	2322	0.0650

94	2323	0.0630
95	2324/1	0.0090
96	2324/2	
97	2390	0.0520
98	3181	0.0670
99	3183	0.0060
100	3184	0.0600
101	3185	0.0630
102	3177	0.0560
103	3175	0.0060
104	3172/1	0.0240
105	3172/2	
106	3170	0.0580
107	3165	0.0400
108	3166	0.0390
109	3167	0.0420
110	3152	0.0090
111	417	0.0370
112	418	0.0520
113	419	0.0020
114	415/1	0.0780
115	416/1	
116	394	0.0760
117	395	0.0420
118	396	0.0990
119	368	0.0210
120	369	0.0420
121	373	0.0600
122	374	0.0500
123	375	0.0080
124	363	0.0050
125	364	0.0860
126	831	0.0640
127	832	0.0310
128	837	0.0600

129	838	0.0080
130	866	0.0020
131	870	0.0940
132	889	0.0610
133	1058	0.0600
134	1059	0.0420
135	1061	0.0010
136	1062	0.0560
137	1063	0.0010
138	1065	0.0320
139	1064	0.0100
140	1070	0.0420
141	1072	0.0390
142	1038/2	0.0580
143	1037	0.0490
144	1036	0.0040
145	1035/2	0.0350
146	1032/1	0.0240
147	1032/2	
148	1030	0.0420
149	1031	0.0520
150	1021	0.0210
151	1022	0.0210
152	1018/1	0.1880
153	1017	0.0210
154	1561/1	0.0210
155	1618	0.0720
156	1562	0.0790
157	1564	0.0320
158	1565	0.0580
159	1566	0.0090
160	1558/1/1	0.0600
161	1558/1/2	
162	1551	0.0210
163	1548	0.0960

164	1545	0.0870
165	1547	0.0020
166	1549/1	0.0230
167	1549/2	0.0340
168	1523	0.0020
169	1526/1	0.0100
170	1527	0.1160
171	1504	0.0010
172	1505	
173	1494	
174	1486	0.1420
175	1487	
176	1493	
177	1492	0.0020
178	1506	0.0630
179	1507	0.0160
180	1484	0.0510
181	1474	0.0710
182	1476	0.0020
183	1475	0.0150
184	2841	0.0730
185	2842	0.0480
186	2846/2	0.1340
187	2855/2/1	0.0220
188	2856/3	0.0010
189	2858/1	
190	2858/2	
191	2858/3	0.0090
192	2858/4	
193	2858/5	
194	2859/1	
195	2859/2	0.0060
196	2874/1	
197	2874/2	0.0890
198	2871	0.0210
199	2869	0.0050
200	2860	
201	2861	0.0990
202	2862	
203	2875/1/1	
204	2875/1/2	0.0420
205	2873	
कुल योग रकबा हे.में-		9.5930

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कैलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2379-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - कुंदहरी खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 2.6850 हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	4/4/4/2	0.0840
2	4/3/3	0.0590
3	4/2/2	0.0400
4	3/1	0.0200
5	5/1	
6	5/2	0.0600
7	5/3	
8	6	0.0940
9	53/1	0.0350
10	53/2	0.0330
11	54	0.0560
12	55	0.0250
13	77/3	0.0110
14	70	0.0120
15	71	0.0580
16	72/2	0.0540
17	87	0.0500
18	85	0.0590
19	90	0.0360
20	91	0.0680
21	92	0.0510
22	386/1	0.0250
23	387/1	0.1050

24	381	0.0310
25	382	0.0630
26	368	0.0080
27	367/3	0.0420
28	367/2	
29	367/1/2	
30	367/1/1	
31	380	0.1570
32	379	0.0080
33	388/2	0.0980
34	388/1	0.0990
35	362	0.1600
36	363/2	0.0080
37	360	0.0940
38	358/1	0.2020
39	355	0.1870
40	354	0.0700
41	352/1	0.1500
42	345/2	0.0290
43	340/1	0.0200
44	340/2	0.0160
45	341/3	0.0150
46	341/6	0.0300
47	343	0.0300
48	344	0.0300
49	339	0.0180
50	329/1	0.0060
51	327/1	0.0200
52	327/2	0.0150
53	328/1	0.0100
54	328/2	0.0340
	कुल रकबा हे.में-	2.6850

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2380-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - अकही

(घ) क्षेत्रफल- 2.089 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	71	0.0750
2	70	0.0470
3	80	0.0420
4	82	0.0520
5	83	0.0060
6	89	0.0230
7	90	0.0130
8	88	0.0940
9	94	0.0350
10	95	0.0330
11	96	0.0570
12	42/2/1/2/6	0.1050
13	153	0.0540
14	154	0.0650
15	158	0.0340
16	159	0.0420
17	160/3	0.0180
18	161	0.0940
19	160/1	0.0080
20	160/2	0.0040
21	162	0.0240
22	164/2/1	0.1850

23	164/2/2/1	0.2200
24	195/2	0.0180
25	225/1/1/1	0.0720
26	208/3	0.0370
27	221/1/1	0.1500
28	220/1/1	0.1030
29	218/2/2/1	0.0500
30	208/2/2/1	0.0270
31	218/2/2/2	0.0270
32	208/2/2/2	0.0110
33	208/1	0.0740
34	218/1	0.1530
35	208/4	0.0370
	कुल योग रकबा हे.में-	2.0890

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2381-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - बांधीमौहार
(घ) क्षेत्रफल- 1.4790 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	670/2/3/1	0.0270
2	670/2/3/2	0.0270
3	670/2/3/3	0.0270
4	967/1	0.2610
5	968/1	0.0180
6	969	0.0130
7	970/1	0.0900
8	970/2/1	0.0570
9	971/1	0.0470
10	971/2/1	0.0240
11	972/1	0.0700
12	972/2	0.0700
13	973/2	0.1310
14	973/4/1	0.0630
15	973/4/2	0.0630
16	975/2	0.0210
17	975/3	0.0060
18	973/3/1	0.0880
19	709/2/1	0.0220
20	704/3/1/1	0.1660
21	702/1	0.1660
22	700/1	0.0220
	कुल योग रकबा हे.में-	1.4790

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर एवं उमरी माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-6-अ-82-भू-अर्जन-जबेरा-2023-24

दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अधिसूची धारा-19

भूमि का वर्णन

क.-	जिला	- दमोह
ख.-	तहसील	- जबेरा
ग.-	ग्राम	- पिपरिया सिंगौरगढ़
घ.-	लगभग क्षेत्रफल	- 1.741 हेक्ट.

स. क्र.	खसरा क्र.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4
1	247	0.25	0.084
	246	0.29	0.117
	185	0.29	0.036
2	243/1	0.47	0.018
3	243/2	0.46	0.018
4	242	0.27	0.084
5	147/1/1/1	2.02	0.005
6	147/1/1/2	0.4	0.005
7	147/1/2	0.54	0.011
	147/1/3	0.41	0.011
8	147/1/4	0.54	0.011
	147/1/5	0.4	0.011
	147/1/6	0.41	0.011
9	147/2	0.8	0.082
10	147/3	0.82	0.082
11	147/4	1.62	0.082
12	147/5/1	1.23	0.041
13	147/5/2	0.4	0.041
14	103/1	0.01	0.002
15	103/2	0.65	0.092
16	103/3	0.53	0.080
17	103/4	0.3	0.036
18	102	0.42	0.120
19	36/1	0.41	0.045
	36/2	0.4	0.045
20	41	0.28	0.066
21	38	0.27	0.072
22	45	0.87	0.132
23	44/1	0.27	0.045
24	44/2	0.28	0.045
25	46	0.41	0.027
26	47	0.38	0.078
27	40	0.5	0.017
28	151	0.36	0.007
29	183	0.15	0.072
	29 कित्ता	18.11	1.741

क्र.-7-अ-82-भू-अर्जन-तेदूखेड़ा-2024-25

दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1 भूमि का वर्णन

जिला	- दमोह
ख.- तहसील	- जबेरा
ग.- ग्राम	- पारना
घ. - लगभग क्षेत्रफल	- 6.725 हेक्ट.

स.क्र.	खसरा क्र.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4
	ग्राम - पारना		
1	384/1/1	0.640	0.026
2	384/1/2/1	0.210	0.008
	384/1/2/2	0.220	0.008
4	384/1/2/3	0.210	0.008
5	322	0.52	0.152
6	321	1.04	0.180
7	319	0.97	0.056
	294	0.76	0.072
8	293	1.36	0.112
9	313/524	0.46	0.040
10	313	0.46	0.180
11	300	0.78	0.208
12	198	0.29	0.108
13	206/1	0.27	0.068
14	206/2	0.44	0.068
15	212	0.52	0.120
16	223/1	0.14	0.040
17	223/2	0.04	0.040
18	222/1	0.54	0.110
19	222/2	0.53	0.110
20	228	0.85	0.216
	95	0.22	0.092

21	235	0.36	0.068
22	236	0.31	0.288
23	96	0.4	0.095
24	87	0.58	0.148
25	82/1	1.49	0.236
26	80	3.4	0.276
27	78	0.66	0.168
28	72/1/2	0.8	0.154
29	72/3	0.8	0.154
30	72/4	0.8	0.154
31	72/5	0.8	0.154
32	86/1/1	0.48	0.021
33	86/1/2	0.17	0.021
34	86/2	0.4	0.042
35	207	0.42	0.080
36	211/1	0.52	0.060
37	211/2	0.18	0.060
38	314	1.35	0.119
39	318	0.98	0.184
40	386	0.32	0.204
41	93	0.13	0.042
42	320	0.74	0.144
पारना माईनर			
43	322	0.52	0.096
44	324	0.21	0.036
45	325	0.57	0.060
46	326	1.03	0.174
47	329	0.56	0.076
48	343/1	0.4	0.030
49	343/2	0.08	0.030
50	344/1	0.37	0.028
51	344/2	0.4	0.028
52	345	0.22	0.036
53	347	0.17	0.048
54	346	1.15	0.039
55	349	0.44	0.096
56	304/1	0.09	0.037
57	304/2	0.09	0.037
58	304/3	0.18	0.037
59	192	0.66	0.096
60	193	0.76	0.082
61	162	0.21	0.050
62	160/2	0.14	0.075
	159	0.85	0.066
63	158	1.12	0.114
64	169/1	0.43	0.100
65	169/3	0.22	0.100
66	157	1.92	0.252
66 कित्ता		40.35	6.7255

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तैदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. उल्लेखित भूमि के हितवद्द कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तैदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है

क्र.-8-अ-82-भू-अर्जन-जबेरा-2023-24

दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अधिसूची धारा-19

भूमि का वर्णन

क.-	जिला	-	दमोह
ख.-	तहसील	-	जबेरा
ग.-	ग्राम	-	कोरता
घ. -	लगभग क्षेत्रफल	-	2.380 हेक्ट.

स. क्र.	खसरा क्र.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4
1	79/1	0.13	0.020
2	79/2	0.13	0.020
3	80	0.41	0.144
	कोरता माईनर		
4	77/1	0.36	0.096
5	77/2	0.72	0.096
6	72	0.57	0.192
7	70	0.14	0.060
8	71	0.39	0.060
9	67	1.06	0.217
10	110	0.62	0.032
11	111	1.22	0.252
12	51	0.5	0.088
13	112	0.74	0.164
14	52/1	0.27	0.034
15	52/2	0.22	0.034
16	48	0.74	0.096
17	47	0.59	0.124
18	41/1	0.29	0.034
19	41/2	0.14	0.034
20	41/3	0.14	0.034
21	21\1\1	0.12	0.026
22	21\1\2	0.04	0.026
	21\2\2	0.05	0.026
23	21\2\1	0.04	0.026
24	22	0.99	0.200
25	75	0.98	0.160
26	62	1.18	0.076
27	68	0.22	0.009
	27 कित्ता	13.00	2.380

क्र.-9-अ-82-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2024-25

दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1 भूमि का वर्णन

क.-	जिला	- दमोह
ख.-	तहसील	- जबेरा
ग.-	ग्राम	- डेलनखेड़ा
घ.-	लगभग क्षेत्रफल	- 1.572 हेक्ट.

स. क्र.	खसरा क्र.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4
1	368	0.24	0.051
2	366	0.14	0.063
3	365/1	1.12	0.130
4	365/2	1.12	0.130
5	164/1	0.32	0.026
6	164/2	0.3	0.026
	164/3	0.3	0.026
	165	0.31	0.068
7	139	1.03	0.099
8	140/1	0.41	0.028
	140/2	0.4	0.028
9	154	1	0.149
10	153/1	0.18	0.043
11	153/2	0.54	0.043
12	145	0.79	0.087
13	146/1	0.58	0.043
14	146/2	0.14	0.043
15	147/1	0.64	0.036
16	147/2	0.2	0.036
17	159	0.86	0.126
18	162	0.35	0.078
19	163	0.58	0.001
20	369	0.16	0.024
21	379	1.09	0.180
	21 कित्ता	12.8	1.572

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
3. भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. उल्लेखित भूमि के हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेदूखेड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-10-अ-82-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2024-25

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

- क.- जिला - दमोह
ख.- तहसील - जबेरा
ग.- ग्राम - वंशीपुर
घ. - लगभग क्षेत्रफल - 3.881 हेक्ट.

स.क्र.	खसरा क्र.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4
	मुख्य नहर		
1	616	0.72	0.063
2	495	1.51	0.114
3	528	1.55	0.174
4	526	1.05	0.030
5	490	0.58	0.135
6	493	0.17	0.045
7	501/2	0.2	0.126
8	500	0.99	0.171
9	404/1	0.41	0.075
10	404/2	0.81	0.075
11	405/1	0.55	0.028
12	405/2	0.55	0.028
13	405/3	0.56	0.028
14	405/4/1	0.16	0.014
15	405/4/2	0.4	0.014
16	489/1	0.3	0.019
17	489/2	0.29	0.019
18	527/1	0.25	0.039
19	527/2	0.25	0.039
20	527/3	0.25	0.039
21	527/4	0.26	0.039

22	534/1	0.36	0.061
23	534/2	1.0	0.061
24	535	0.4	0.060
25	536	0.45	0.072
26	537	0.47	0.087
27	540/1	0.35	0.057
28	540/2	0.34	0.057
29	542	0.37	0.081
ग्राम - वंशीपुर (कोरता माईनर)			
1	863/776	0.32	0.108
2	780/1	0.29	0.046
3	780/2/1	0.18	0.023
4	780/2/2	0.4	0.023
5	780/3	0.29	0.046
6	716	1.8	0.288
7	715/1	0.19	0.055
8	715/2	0.6	0.055
9	715/3	0.4	0.055
10	715/4	0.18	0.055
11	676	0.45	0.084
12	677	0.5	0.120
13	679/1	0.43	0.032
14	679/2	0.22	0.032
15	679/3	0.22	0.032
16	174/1	0.51	0.084
17	174/2	0.51	0.084
18	159	1.29	0.264
19	151	0.06	0.040
20	160/1	0.08	0.012
21	160/2	0.16	0.012
22	173	0.37	0.032
23	779	1.53	0.172
24	788/1	0.15	0.030
25	788/2	0.1	0.030
26	789/1	0.06	0.036
27	789/2	0.07	0.036
28	790	1.38	0.136
57 किता		28.29	3.881

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. उल्लेखित भूमि के हितवद्द कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-6198-भू-अर्जन-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- नवेगांव प0ह0न-54 ब.न.-293 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-32.161 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	280	0.144
2	281	0.004
3	279	0.073
4	276/1	0.053
5	274	0.151
6	275	0.101
7	269	0.067
8	267/4	0.115
9	267/5	0.077
10	264/2	0.008

11	263/1	0.130
12	263/2	0.087
13	263/4	0.015
14	42	0.004
15	35/1	0.183
16	101/1	0.082
17	101/2	0.144
18	103	0.206
19	98/1	0.139
20	93/2	0.058
21	93/3	0.180
22	203/3	0.016
23	90/1	0.115
24	231	0.014
25	232	0.041
26	239/1	0.039
27	227/1	0.098
28	227/2	0.017
29	201	0.087
30	203/1	0.016
31	203/2	0.016
32	204	0.014
33	205	0.010
34	206/1	0.002
35	206/2	0.004
36	165/3/1	0.044
37	165/4/2	0.055

38	165/4/1	0.055
39	115	0.036
40	164/3	0.070
41	164/1	0.072
42	164/5	0.048
43	164/2	0.158
44	46	01.605
45	49	0.611
46	50	0.344
47	301/1	02.012
48	51	0.138
49	53/1	0.873
50	54	01.841
51	40	0.231
52	116	0.020
53	55	0.142
54	57	0.081
55	58	0.202
56	59/3	0.365
57	62/3	0.053
58	59/1/1	0.090
59	62/1/1	0.060
60	59/1/2	0.302
61	62/1/2	0.072
62	59/1/3	0.303
63	62/1/3	0.083
64	59/2	0.320

65	62/2	0.043
66	286/1/1	0.080
67	286/1/2	0.080
68	287/1/1	0.038
69	287/1/2	0.206
70	287/1/3	0.206
71	287/1/4	0.412
72	286/2	0.073
73	287/3	0.292
74	286/3	0.040
75	287/2/1	0.103
76	287/4	0.057
77	287/2/2	0.076
78	287/2/3	0.076
79	288	02.100
80	298	0.971
81	291	01.416
82	311/2	0.190
83	292/1	0.962
84	292/2	0.575
85	295	0.036
86	296	0.324
87	297/1	0.598
88	297/10	0.598
89	297/2	01.020
90	297/3	0.243
91	297/8	01.056
92	297/11	0.242
93	297/12	0.223
94	297/4	0.809
95	297/5	0.526
96	297/6	01.056
97	297/13	0.223
98	301/2	0.154
99	297/7	0.283
100	297/9	0.849

101	297/14	0.244
102	299	0.417
103	300/1	0.097
104	311/1	0.030
105	314/2	0.008
106	314/7	0.202
107	314/9	0.382
108	314/3	0.016
109	314/10	0.090
110	314/5	0.130
111	314/6	0.700
112	314/8	0.148
113	314/11	0.366
114	60/1,60/2	0.140
115	61	0.146
116	165/5	0.005
117	96/1	0.008
	योग :-	कुल रकबा-32.161 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-6200-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	छिन्दवाड़ा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- घाट परासिया प0ह0न-36 ब.न.-317 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-17.717 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	206	0.303
2	208/5/1	0.030
3	208/5/2	0.030
4	208/5/3	0.030
5	214	01.137
6	215/1	0.333
7	218/1/1	0.076
8	222/1	0.170
9	215/2	0.340
10	218/1/2	0.024

11	222/2	0.215
12	215/3	0.340
13	218/1/3	0.024
14	222/3	0.215
15	215/5	0.370
16	218/1/5	0.165
17	221/1	0.020
18	222/5	0.023
19	215/6	0.113
20	216	0.045
21	218/1/6	0.207
22	221/2	0.213
23	217/1	0.404
24	218/1/7	0.084
25	221/3	0.090
26	217/2	0.425
27	218/1/8	0.091
28	221/4	0.062
29	217/3	0.425
30	218/1/9	0.091
31	221/5	0.062
32	217/4	0.425
33	218/1/10	0.090
34	221/6	0.063
35	215/4	0.370
36	218/1/4	0.058
37	222/4	0.150

38	219	0.255
39	253/2	0.330
40	253/4	01.162
41	267/1	0.809
42	267/2	0.623
43	267/3	0.186
44	268/1	0.162
45	268/2	0.161
46	269/1	0.421
47	267/4	0.393
48	266/1	0.450
49	266/2	0.967
50	266/3	0.967
51	269/2	0.910
52	286	0.340
53	289	0.162
54	287	0.798
55	288	0.109
56	290/2	0.439
57	290/3	0.760
	योग :-	कुल रकबा-17.717 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. **अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाडा, जिला-छिन्दवाडा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।**
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग छिन्दवाडा, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-6209-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड़
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-महलपुर प0ह0न-29 ब.न.-456 रा.नि.मं.-सांवरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	153	0.008
2	152/6/2	0.092
3	151/3	0.020
4	151/1	0.020
5	151/5	0.020
6	151/7	0.020
7	139/3	0.042
8	138	0.043
9	134/2	0.045
10	133/4	0.030
	योग :-	कुल रकबा-0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क0 6 में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-6210-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, चीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड़
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम-सारोठ प0ह0न-07 ब.न.-215 रा.नि.मं.-सांवरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.389 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	113/1	0.004
2	112/1	0.014
3	111/6	0.006
4	110/9	0.014
5	110/6	0.046
6	110/7	0.026
7	76/2	0.051
8	110/3	0.010
9	110/2	0.015
10	57/3	0.028

11	76/1	0.054
12	50	0.065
13	58	0.016
14	75	0.040
	योग :-	कुल रकबा-0.389 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क्र0 6 में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 14th August 2024

No. 103-Comp.-2024-CJ-II-1894.- WHEREAS, an enquiry has been ordered to be initiated against Shri Ashutosh Agnihotri, III Civil Judge, Junior Division, Lavkushnagar, District Chhatarpur for showing act of grave misconduct and misuse of powers.

AND, WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Ashutosh Agnihotri, III Civil Judge, Junior Division, Lavkushnagar, Distict Chhatarpur, under suspension with immediate effect with the headquarters at Alirajpur during the period of suspension.

He is further directed to report to the Principal District & Sessions Judge, Alirajpur in compliance of the order.

By order of the High Court,
ASHUTOSH AGRAWAL, Registrar (Vigilance).

Jabalpur, the 10th September 2024

No.114-CJ-II-1179.- WHEREAS, an enquiry has been ordered to be initiated against Shri Pankaj Yadav, XXIII District & Additional Sessions Judge, Indore for showing act of grave misconduct and misuse of powers.

AND, WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Pankaj Yadav, XXIII District & Additional Sessions Judge,

Indore, under suspension with immediate effect with the headquarters at Sheopur during the period of suspension.

He is further directed to report to the Principal District & Sessions Judge, Sheopur in compliance of the order.

By order of the High Court,
VAIBHAV MANDLOI, Principal Registrar
(Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्र.-बी-4425-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-4425-III-10-42-75.- The Judge named in the column No.(3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No.(2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No.(4) for holding Link Court.

S. No.	Place, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sitamau (Mandsaur)	Shri Munendra Singh Verma, Additional Judge to the Court of I District & Additional Sessions Judge, Mandsaur	One Week

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,
रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार
(डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2024

क्र.-C-7114-चार-9-07-2024 पेंशन.- श्रीमती बीनू पिल्लई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम, 42 (1) (ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 3 अगस्त 2024 को प्रस्तुत आवेदन-पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, श्रीमती बीनू पिल्लई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 30 सितम्बर 2024 अपरान्ह से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्र.-B-4229-दो-2-32-2018.-श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश कुमार तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-4231-दो-2-14-2015.-श्रीमती रेणुका कंचन, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार, वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीडित, भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक का एवं दिनांक 6 से 17 फरवरी 2023 तक, का कुल सत्रह दिन का तथा दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक पांच दिन (कुल बाईस दिन) का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-B-4233-दो-2-23-2020.-श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-4237-दो-2-21-2022.-श्री रविन्द्र सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2024 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 24 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2024

क्र.-C-7000-दो-3-420-80-भाग-बारह.- सुश्री भावना साधू, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार-सुश्री भावना साधू की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 266 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 406 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300

दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज - 286 दिवस में नगद भुगतान
- (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - 286 2= 14 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-C-7002-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री महेन्द्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार - श्री महेन्द्र सिंह तोमर, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 276 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 410 अर्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज - 276 दिवस में नगद भुगतान.
- (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - 48/2= 24 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-C-7004-दो-2-61-2021.-श्री पी.सी.गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 24 से 26 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी.गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-4505-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री सुबोध कुमार जैन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री सुबोध कुमार जैन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 29 अगस्त 2024 को उनके खाते में 169 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 432 अर्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे :-

- (i) अर्जित अवकाश के एवज - 169 दिवस में नगद भुगतान.
- (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - 262 (262/2= 131 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).

क्र.-B-4507-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6125, दिनांक 12.12.2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-B-4509-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन

को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री कुलकर्णी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को उनके खाते में 273 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 258 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज | - | 273 दिवस |
| | में नगद भुगतान. | | |
| (ii) | अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज | - | 54/2= 27 |
| | में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. | | |

क्र.-B-4511-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री तिवारी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को उनके खाते में 162 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 498 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | | | |
|------|---|---|------------|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज | - | 162 दिवस |
| | में नगद भुगतान. | | |
| (ii) | अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज | - | 276/2= 138 |
| | में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. | | |

क्र.-B-4517-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6125, दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-B-4521-दो-2-32-2023.-श्री संजीव कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 3 जून 2022 से दिनांक 2 जून 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.-B-4523-दो-2-40-2024.-श्री युगल रघुवंशी रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री युगल रघुवंशी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री युगल रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र.-C-7033-दो-2-23-2024.-श्री बी. एल. प्रजापति,

प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. प्रजापति, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. प्रजापति, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7035-दो-2-11-2024.-श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 9 से 12 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 7 से 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7037-दो-2-64-2014.- श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7039-दो-2-42-2022.-श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र.-C-7041-दो-2-53-2022.-श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 23 से 24 अगस्त 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7043-दो-2-48-2021.-श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7045-दो-2-13-2019.-श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 1 सितम्बर 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7047-दो-2-26-2022.-श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7049-दो-2-13-2015.-श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 12 से 13 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7051-दो-2-56-2021.-श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-C-7053-दो-2-23-2020.-श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7055-दो-2-65-2018.-श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.—C-7062-दो-2-33-2023.—श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, डी.आर.—कम—पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्र.—अवकाश—.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 27 अगस्त से 2 सितम्बर 2024 तक सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.